प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
14.07.2025 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

मुख्य समाचार

- **मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश की ऋण सीमा बढ़ाने और भारी वर्षा से हुए नुकसान के लिए राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने का केन्द्र से किया आग्रह।**
- **हिमाचल सेब उत्पादक संघ वन भूमि से सेब कटान के फैसले को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट से की पुनर्विचार की मांग।**
- **स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने मंडी ज़िला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व पुनर्वास कार्यों का लिया जायज़ा–प्रभावितों को हरसंभव सहायता का दिया आश्वासन।**
- **प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम लगातार जारी–मौसम विभाग ने 20 जुलाई तक भारी वर्षा की जताई संभावना।**
- **किन्नौर ज़िला की प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा कल से शुरू–सभी तैयारियां पूरी।**

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री को हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति से अवगत करवाया और प्रदेश की ऋण सीमा बढ़ाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारी बारिश के कारण प्रदेश में हुए भारी नुकसान से भी वित्त मंत्री को अवगत करवाया और केंद्र सरकार से राज्य को सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त मंत्रालय में प्रदेश के लम्बित विभिन्न मामलों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की। इस बीच मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से भी भेंट की और हिमाचल प्रदेश में हवाई सम्पर्क को सुदृढ़ करने को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से दिल्ली–शिमला–धर्मशाला और धर्मशाला–शिमला–दिल्ली हवाई उड़ानों का संचालन नियमित रूप से करने का आग्रह किया जो वर्तमान में केवल तीन दिन ही संचालित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि नियमित उड़ाने नहीं होने से पर्यटकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने धर्मशाला में नाइट लेडिंग की सुविधा शुरू करवाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की स्थिति की जानकारी दी और भूमि अधिग्रहण की अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए विशेष सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में हवाई सम्पर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चार नए हैलीपोर्ट के निर्माण का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर शिमला में डॉर्नियर प्रकार के विमानों के संचालन का प्रस्ताव भी दिया।

अवैध कटान

प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शिमला जिले में वन भूमि से कब्जे हटाने के लिए वन व राजस्व विभाग ने मुहिम को तेज कर दिया है। कोटखाई और कुमारसैन में वन भूमि पर बने बागीचों में सेब से लदे पेड़ों को काटा गया है जिससे सेब बागवानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादक संघ और किसान सभा ने सेब कटान की कार्रवाई को अवैज्ञानिक करार दिया है और हाई कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के साथ सरकार से कोर्ट में सही पक्ष रखने की मांग की है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में किसान नेता राकेश सिंघा ने कहा कि वन भूमि से कब्जे हटाने के नाम पर प्रदेश के किसानों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। राकेश सिंघा ने राज्य सरकार पर इस संबंध में दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया।

"हम माननीय सामान्य उच्च न्यायालय से उम्मीद करते हैं कि जो अपने मोशन पर ऐसा फैसला उन्होंने दिया है उस पर वो पुनर्विचार करें जिससे जो पेड़ का कटान है, वह समाप्त हो । पेड़ का कट कटान हिमाचल प्रदेश में खास तौर पर जो सबसे बड़ी आर्थिकी है सेब की ,पेड़ कटना का मतलब है हिमाचल प्रदेश का स्वयं कटना, हिमाचल प्रदेश की सरकार का दायित्व बनता था कि जो प्रस्ताव उन्होंने विधानसभा में पारित किया, वह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगे लेकिन हाईकोर्ट में ऐसा पक्ष नहीं रखा गया यह बहुत दुर्भाग्य है।"

उन्होंने कहा कि बागवान सेब के पौधों के कटान को स्वीकार नहीं करेंगे और इसके खिलाफ जनांदोलन किया जाएगा।

जगत सिंह नेगी

इस बीच राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि जो लोग प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें कानूनी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। जगत सिंह नेगी ने कहा कि यह फैसला जनवरी में आ चुका था और राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर कर कुछ समय तक पेड़ों की कटाई पर राहत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने यह अर्जी खारिज कर दी है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि वन अधिकार कानून और अतिक्रमण के कानून अलग–अलग हैं। एफआरए कानून 2008 से लागू है, लेकिन बहुत से लोग अपना दावा समय पर पेश नहीं कर सके। ऐसे में सरकार की तरफ से कोई विरोधाभास नहीं है।

शांडिल

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज मंडी जिला के सराज में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वहां हुए नुकसान और राहत व पुर्नवास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों से भेंट की और उन्हें राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सराज क्षेत्र को सात करोड़ रूपए तुरंत प्रभाव से जारी किए गए हैं और राजस्व अधिकारियों को सभी प्रकार के नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों को फिर से बसाने के लिए वन टाईम पॉलिसी लाने पर विचार करेगी। शांडिल ने कहा कि आपदा के बाद दुर्गम क्षेत्रों तक बुनियादी स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और थुनाग व जंजैहली क्षेत्रों में अभी तक 13 हजार 3 सौ 50 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है।

अनुराग ठाकुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वे मंडी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार से अधिक से अधिक एरिया और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बजट की मांग करेंगे ताकि उस बजट को केवल आपदा प्रभावित क्षेत्रों पर ही खर्च किया जा सके। उन्होंने आज आपदा प्रभावित क्षेत्र थुनाग का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत व पुनर्वास का कार्य हम सबकी प्राथमिकता है।

इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार भी मौजूद रहे।

कुलदीप पठानिया

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि विधायी समितियां विधायिकाओं की रीढ़ है जो विस्तृत विचार विमर्श और प्रभावी निगरानी को सक्षम बनाती है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक में संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। कुलदीप पठानिया ने विधानमंडलों में अनुसंधान और सचिवालय सहायता में वृद्धि करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने भ्रामक जानकारी के लिए विभागों को जिम्मेवार व जवाबदेह बनाने और मीडिया की भागीदारी व पारदर्शिता को मजबूत करने की जरूरत बताई। गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने समिति प्रणाली के सुदृढीकरण विषय की समीक्षा के लिए सात राज्यों के पीठासीन अधिकारियों की समिति का गठन किया है जिनमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, सिक्कम, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी शामिल है।

मौसम

प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 20 जुलाई तक प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि आज और कल कांगड़ा, मंडी व सिरमौर जिले में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला और सोलन जिले में भी भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है।

***"14* जुलाई से लेके 20 जुलाई तक संभावना ये है कि प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में बारिश का क्रम जारी रहेगा। इसी दौरान ऊपरी क्षेत्रों में वेरी हेवी स्नोफॉल होने की संभावना है जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी और सिरमौर यह पर ऑरेंज अलर्ट है, 14 –15 जुलाई के लिए और बाकी डिस्ट्रिक्ट जिसमें ऊना,बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला है सोलन, यहां पर एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल हो सकती है। जिसको देखते हुए हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। येलो कैटेगरी में। 16 जुलाई से 20 जुलाई तक जो क्रम है जारी रहेगा। पर इसमें भी जो ईस्टरीच भी काफी है और ऊपर केवल पर वेस्टर्न लेवल भी सक्रीय है। इसके चलते संभावना ये है कि जैसे आज 14, 15 जुलाई को कई क्षेत्रों में बारिश होगी और जो हाई रिचीज लाहुल स्पीति और कुल्लू में कई स्थानों हिमपात भी हो सकता है।"**

प्रदेश में इस मॉनसून सीजन में अभी तक सामान्य से 19 फीसदी से अधिक बारिश दर्ज की गई है और सबसे अधिक मंडी जिले में सामान्य से 91 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है। भारी वर्षा, भूस्खलन और बादल फटने के कारण प्रदेश में अभी भी एक सौ 92 सड़कें यातायात के लिए अवरूद्ध है। इसके अलावा 65 बिजली के ट्रांसफार्मर और सात सौ 45 पेयजल योजनाएं भी बंद हैं। राज्य में वर्षा जनित घटनाओं में अब तक एक सौ 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जबकि 35 अभी भी लापता है।

किन्नर कैलाश यात्रा

किन्नौर जिला प्रशासन ने 15 से 30 अगस्त तक चलने वाली किन्नर कैलाश यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

15 जुलाई से हमारी जो किन्नर कैलाश होती है उसकी शुरूआत की जाएगी। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो मेंडेटरी है रजिस्ट्रेशन प्लस जो कंपरलसरी मेडिकल चैकअप है। उसके लिए तांगलिंग एरिया जो हैं जहां हमारे एंटरी प्वाइंट हैं वहां पर सीसीटीवी ऐज वेल ऐज मेडिकल चेकअप के जो सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन जरूरी है जो ग्रीन टैक्स जो लोकल पंचायत द्वारा लगाया जा रहा है उसका मकसद यही है कि

कहीं न कहीं क्योंकि ये जो एनवायरमेंट है बहुत परेसटीम नेचुरल एनवायरमेंट है। यहां पर सोलिड वेस्ट कूड़ा करकट न फैलाएं उससे बचाव के लिए ग्रीन टैक्स लगाया जा रहा है।

मुख्य समाचार एक बार फिर

- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश की ऋण सीमा बढ़ाने और भारी वर्षा से हुए नुकसान के लिए राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने का केन्द्र से किया आग्रह।
- हिमाचल सेब उत्पादक संघ वन भूमि से सेब कटान के फैसले को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट से की पुनर्विचार की मांग।
- स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने मंडी ज़िला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व पुनर्वास कार्यों का लिया जायज़ा–प्रभावितों को हरसंभव सहायता का दिया आश्वासन।
- प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम लगातार जारी–मौसम विभाग ने 20 जुलाई तक भारी वर्षा की जताई संभावना।
- किन्नौर ज़िला की प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा कल से शुरू–सभी तैयारियां पूरी।

.....